

(2015) 1. एससीआर। 1

क

दीवान सिंह

वी।

ख

भारत का जीवन बीमा निगम और

अन्य

ग

(सिविल अपील नंबर, 2010 का 3655) जनवरी 5, 2015

[विक्रमजीत सेन और प्रफुल्ल सी। पैंट, जे. जे.]

घ

सेवा कानून: अनिवार्य सेवानिवृत्ति-निधियों का दुरुपयोग-13.8.1990 को अपीलार्थी-कैशियर के साथ पॉलिसी धारक द्वारा रु। 533 का जमा लेकिन एलआईसी के साथ जमा नहीं की गई राशि-रुपये का अस्थायी गबन। 533/- 13.08.1990 से 27.11.1990 की अवधि के लिए और रुपये की फोर्जिंग प्रविष्टि। 533/- कैशियर द्वारा दिनांक 13.08.1990 की खाता बही की कार्बन कॉपी में-सेवा से हटाने का आदेश-उच्च न्यायालय ने सेवा से हटाने के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की

ङ

सजा को प्रतिस्थापित किया-अपील पर, आयोजित:

प्रभारी की प्रकृति के मद्देनजर, जिसमें कैशियर को दोषी पाया गया था, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को कठोर और अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है-ऐसे मामलों में, अदालतों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है।

च

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने

छ

हेल्ड: अपीलकर्ता की दलील यह थी कि राशि उसके द्वारा 13.8.1990 को जमा नहीं की जा सकती थी क्योंकि उस दिन पॉलिसी धारक द्वारा वास्तव में भुगतान की गई नकदी कम थी और अपीलकर्ता की ओर से इस तरह का कार्य अलाव था। यह स्पष्टीकरण आश्वस्त नहीं था, क्योंकि कैशियर ने काउंटर पर नकदी की गिनती किए बिना रसीद जारी नहीं की होगी। दूसरे, अपीलार्थी की ओर से किया गया कृत्य अलाव था, उसने रुपये की जाली प्रविष्टि नहीं की होगी। 533/- खाता

ज

बही की कार्बन कॉपी में वह

एट 13.8.1990 को एंट्री नोस के बीच। 12 और 13। जैसे कि

2 सुपर कोर्स रिपोर्ट = [2015] 1 एससी @आर।

- क इस तरह, अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए जांच अधिकारी की खोज को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को दोषी पाए जाने के आरोप की प्रकृति को देखते हुए सजा को कठोर या असम्मानजनक नहीं कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए। गलत तरीके से ली गई राशि छोटी या बड़ी हो सकती है; यह गलत व्यवहार का कार्य है जो प्रासंगिक है। [पारस 5,6,7 और 11] [4-जी; 5-ए-बी, डी; 7-बी]
- ख संभागीय नियंत्रक, एनकेआरटीसी बनाम एम। अमरेश (2006) 6 एससीसी 187:2006 (3) सप्ला। एससीआर 585; डिवीजनल कंट्रोलर, केएसआरटीसी (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) बनाम एटी। माने (2005) 3 एससीसी 254;
- ग निरंजन हेमचंद्र सशित्तल और अनर। वी। महाराष्ट्र राज्य (2013) 4 एससीसी 642:2013 (4) एससीआर 767; राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्न। वी। बजरंग लाल (2014) 4 एससीसी 693:2014 (3) एससीआर 782; नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ बनाम कृष्णन बिहार और ओआरएस। (1996) 2 एससीसी 714:1996 (2) एससीआर 827-पर निर्भर।
- घ केस लॉ संदर्भ:
- ङ 2006 (3) सप्ला। एससीआर 585 पैरा 8 पर निर्भर  
(2005) 3 एससीसी 254 पैरा 9 पर निर्भर
- च 2013 (4) एससीआर 767 पैरा 10 पर निर्भर  
2014 (3) एससीआर 782 पैरा 11 पर निर्भर  
1996 (2) एससीआर 827 पैरा 11 पर निर्भर
- छ सिविल अपीलीय न्यायाधिकरण: सिविल अपील सं।  
2010 का 3655।
- ज निर्णय और आदेश से दिनांक 27-08-2009 को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के विशेष अपील सं। 1999 का 1167।  
अपीलार्थी के लिए गौरव अग्रवाल।

दीवान सिंह वी। जीवन बीमा निगम 3

क

भारत का

कैलाश वासदेव, ए. वी. उत्तरदाताओं के लिए रंगम, बड्डी ए। रंगनाधन।

ख

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

ग

प्रफुल्ल सी: पेंट, जे. 1। यह अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक द्वारा पारित 27.8.2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, विशेष अपील संख्या में। 1999 का 1167, जिसमें कहा गया कि अदालत ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी है, और सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए निष्कासन की सजा को प्रतिस्थापित किया है।

2। हमने पार्टियों के लिए सीखा वकील सुना है और रिकॉर्ड पर कागजात का दुरुपयोग किया है।

घ

3। संक्षेप में कहा गया है, तथ्य यह है कि अपीलकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद "एलआईसी" के रूप में संदर्भित) के साथ एक खजांची था और बिलासपुर, जिला रामपुर में यू. पी. में तैनात था। एक पॉलिसी धारक, भोगराज सिंह ने अपीलकर्ता के साथ 13.8.1990 को छमाही बीमा प्रीमियम के लिए रु। 533/- की राशि जमा की, लेकिन वही एलआईसी के पास जमा नहीं किया गया और न ही 27.11.1990 तक पॉलिसी धारक के खाते में जमा किया गया, हालांकि अपीलकर्ता द्वारा 13.8.1990 को एक रसीद जारी की गई थी। यह प्रतीत होता है

ङ

कि जब एलआईसी एजेंट ने अपना कमीशन जमा किए गए प्रीमियम से बाहर नहीं निकाला, और इस संबंध में पूछताछ की, तो अपीलकर्ता द्वारा रु. 15.90/- के विलंब शुल्क के साथ रु. 533/- की पूर्वोक्त राशि जमा की गई, और प्रविष्टि की गई

च

28.11.1990 को कैश रजिस्टर में। इसके अलावा, बैंक डेट पर लेज़र शीट में एक जाली प्रविष्टि की गई थी। अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त कदाचार के संबंध में, उस पर 29.4.1991 को दो मामलों में, अर्थात् रु। 533/- का अस्थायी गबन किया गया था। 13.8.1990 से 27.11.1990 की अवधि के लिए, और एंटी नोस के बीच 13.8.1990 की खाता बही की कार्बन कॉपी में रु. 533/- की फोर्जिंग प्रविष्टि। 12 और 13।

छ

विभागीय जांच के निष्कर्ष पर, अपीलकर्ता को दोषी पाया गया, और जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ सेवा दी गई, जिसके बाद उसे 21.1.1992 के आदेश की सेवा से हटा दिया गया। विभागीय अपील प्रतीत होती है

ज

4 सुपर कोर्स रिपोर्ट-[2015] 1 एस. सी. आर.

क 22.2.1992 को संबंधित प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया।

ख 4. सेवा से हटाने के आदेश और अपीलकर्ता को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने सिविल विविध रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 का 10308 जिसे 6.9.1999 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। सीखे हुए एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश से दुखी होकर, नियोक्ता (यानी) द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष विशेष अपील दायर की गई। --एलआईसी।)। डिवीजन बेंच, पक्षों को सुनने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता के पास कॉम है अपनी गलती को कवर करने के लिए जालसाजी को मिटाया, और आंशिक रूप से सेवा से हटाने के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को प्रतिस्थापित करके अपील की अनुमति दी। अपीलार्थी-कर्मचारी ने विशेष अवकाश याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा अनुपातहीन, अनुचित और कठोर है। इस न्यायालय द्वारा 19.4.2010 को अवकाश दिया गया था।

घ 5. अपीलकर्ता के लिए सीखे गए वकील श्री गौरव अग्रवाल ने भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 23 पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो निम्नानुसार है: -

ङ "23। सेवा का त्याग। - इस्तीफा या बर्खास्तगी या

ह हटाने या समाप्ति या एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति

च निगम की सेवा से कर्मचारी अपनी पूरी पिछली सेवा को जब्त कर लेगा और परिणामस्वरूप पेंशन लाभ के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगा।

छ अपीलकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह एक छोटी राशि के अस्थायी गबन का मामला है, जैसे वेतन वृद्धि रोकने की मामूली सजा आदि। न्याय के सिद्धांतों से मिला होगा। हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा 13.8.1990 को राशि जमा नहीं की जा सकती है क्योंकि उस दिन पॉलिसी धारक द्वारा वास्तव में भुगतान की गई नकदी कम थी, क्योंकि अपीलकर्ता की ओर से इस तरह का कार्य अलाउड था।

ज 6. हमने उपरोक्त पर विचारशील विचार दिया है

दीवान सिंह बनाम जीवन बीमा निगम = 5

क भारत का [प्रफुल्ला सी। पैंट, जे.]

ख अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया। सामने रखा गया स्पष्टीकरण ठोस प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कैशियर ने काउंटर पर नकदी की गिनती किए बिना रसीद जारी नहीं की होगी। दूसरे, अधिनियम में अपीलकर्ता का हिस्सा अलाभकारी था, उसने प्रविष्टि नोस के बीच 13.8.1990 को खाता बही की कार्बन कॉपी में रु. 533/- की जाली प्रविष्टि नहीं की होगी। 12 और 13। इस प्रकार, हमारी राय में अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए जांच अधिकारी की खोज को एजी नहीं कहा जा सकता है रिकॉर्ड पर सबूत दर्ज करें।

ग 7. जहां तक सजा की मात्रा से संबंधित तर्क, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नियम 23 के मद्देनजर पेंशनरी लाभों को जब्त किया जाता है, ऊपर उद्धृत किया गया है, हम सजा को कठोर या अनुपातहीन नहीं पाते हैं। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को दोषी पाए जाने के आरोप की प्रकृति को देखते हुए अपराधबोध। बार-बार, इस न्यायालय ने लगातार माना है कि ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए।

घ 8. डिवीजनल कंट्रोलर, एनकेआरटीसी बनाम एम। अमरेश में, इस न्यायालय ने, निर्णय के पैरा 18 में इस बिंदु पर विचार व्यक्त किए हैं:

ङ "तत्काल मामले में, धन का दुरुपयोग

अपराधी कर्मचारी केवल 360.95 रुपये था। यह न्यायालय

च उस दंड पर विचार किया है जो निगम के धन का दुरुपयोग करने वाले और कारकों पर विचार करने के लिए दोषी कर्मचारियों को दिया जा सकता है। यह

न्यायालय ने निर्णय के एक क्षेत्र में आयोजित किया कि नुकसान

छ आत्मविश्वास प्राथमिक कारक है न कि मात्रा

धन का दुरुपयोग और वह सहानुभूति या

उदारता एक कारक नहीं हो सकता है जो अभेद्य है

ज कानून। जब किसी कर्मचारी को तीर्थयात्रा का दोषी पाया जाता है या

निगम के धन का दुरुपयोग, कुछ भी नहीं है

निगम में विश्वास या विश्वास खोने में गलत

एक कर्मचारी और बर्खास्तगी की सजा देना। 1 में। (2006) 6 एससीसी 187।

6 सुपर कोर्स रिपोर्ट = [2015] 1 एस. सी. आर.

क ऐसे मामलों में, न्यायिक मंचों की ओर से उदारता या गलत सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं है और इसलिए सजा की मात्रा के साथ हस्तक्षेप..... " 9. संभागीय नियंत्रक में, केएसआरटीसी (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) बनाम ए. टी.

ख मानों? जिसमें बेहिसाब राशि केवल रु. 93/- थी

कोर्ट ने पैरा 12 में अपनी राय निम्नानुसार व्यक्त की:

ग "सजा की मात्रा के सवाल पर आते हुए, किसी को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि यह गलत तरीके से गबन की गई राशि नहीं है जो सजा देने के लिए एक प्राथमिक कारक बन जाता है; इसके विपरीत, यह आत्मविश्वास का नुकसान है जिसे ध्यान में रखा जाने वाला प्राथमिक कारक है। हमारी राय में, जब किसी व्यक्ति को निगम के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है, तो निगम में ऐसे व्यक्ति पर विश्वास या विश्वास खोने और सजा देने में कुछ भी गलत नहीं है बर्खास्तगी "।

घ 10. निरंजन हेमचंद्र सशित्तल और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में ' , इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 25 में निम्नलिखित टिप्पणियों का पालन किया है: -

ङ .... " वर्तमान परिदृश्य में, अर्थव्यवस्था के मज्जा को नष्ट करने की क्षमता के लिए भ्रष्टाचार का इलाज किया गया है। ऐसे मामले हैं जहां राशि छोटी है, और कुछ मामलों में, यह बहुत अधिक है। इस तरह के मामले में अपराध की गंभीरता, हमारे विचार में, रिश्तों की मात्रा के आधार पर स्थिति नहीं की जानी है। लाभ के बदले में पक्ष बढ़ाने के लिए आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करने का रवैया सामूहिक के खिलाफ अपराध है और मूल सिद्धांतों के लिए एक अनात्मा है

च लोकतंत्र, इसके लिए व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। यह कानून के नियम में एक लाइलाज सहमति बनाता है... "

2। (2005) 3 एससीसी 254।

छ 3। (2013) 4 एससीसी 642

ज 4, (2014) 4 एससीसी 693

5। (1996) 2 एससीसी 714

क

भारत का [प्रफुल्ला सी। पैंट, जे.]

ख

11. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य वी। बजरंग लाई में, इस अदालत ने, नगर समिति, बहादुरगढ़ बनाम कृष्णन बिहारी और अन्य के मामले के बाद, "यह माना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में बर्खास्तगी के अलावा कोई अन्य सजा नहीं हो सकती है। यह आगे आयोजित किया गया है कि ऐसे मामलों में दिखाई गई कोई भी सहानुभूति सार्वजनिक हित के लिए पूरी तरह से अनियंत्रित है और इसका विरोध किया जाता है। गलत तरीके से ली गई राशि छोटी या बड़ी हो सकती है; यह गलत व्यवहार का कार्य है जो प्रासंगिक है। मैं

ग

कहा मामला (राजस्थान एसआरटीसी), प्रतिवादी/कर्मचारी को सेवा से हटाने की सजा दी गई थी। वर्तमान मामले में यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति है। उत्तरदाताओं के लिए सीखे गए वकील ने प्रस्तुत किया कि पहले के अवसर पर, अपीलकर्ता को टिकटों के अपस्फीति के संबंध में, उसके कदाचार के लिए मामूली सजा दी गई थी। और अब वह दूसरी बार दोषी पाया गया है।

घ

12. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर उपरोक्त परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर है, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, अपील को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। देविका गुजराल अपील खारिज।

ङ

च

छ

ज